बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 91 ● नई दिल्ली ● शनिवार 17 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

क्रॉकरी बनाने वाली फैक्टरी की लिफ्ट टूटने से दो मजदूरों की मौत, कारखाना सील; लापरवाही का मामला दर्ज

नई दिल्ली। समयपुर बादली इलाके में क्रॉकरी बनाने वाली फैक्टरी की लिफ्ट टूटने से दो मजदूरों हरिओम (32) और संजय मिश्रा (45) की मौत हो गई। पुलिस ने फैक्टरी सील कर दी है। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया है और लिफ्ट टूटने के कारणों की तकनीकी जांच कर रही है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 14 जनवरी की शाम करीब 5.20 बजे पुलिस को समयपुर बादली में एक फैक्टरी के लिफ्ट टूटकर गिरने और इसमें दो मजदूरों के घायल होने की जानकारी मिली। गली नंबर नौ में नेहा इंटरप्राइजेज नाम से क्रॉकरी बनाने वाली फैक्टरी में हादसा हुआ था। पुलिस को पता चला कि घायलों पास के अस्पताल में लेकर गए हैं, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।

इंदौर में दूषित पेयजल पीड़ितों से मिलेंगे राहुल गांधी, सम्मेलन को प्रशासन की 'ना' : कांग्रेस

नई दिल्ली। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से उल्टी-दस्त प्रकोप के कारण कई लोगों की मौत के बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को शहर के पीड़ित परिवारों और मरीजों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आठ से 10 मरीजों की हालत बेहद गंभीर है। उन्होंने बताया कि गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचकर निजी क्षेत्र के बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे और उल्टी-दस्त के प्रकोप के कारण भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हालजानेंगे। पटवारी ने बताया कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीरथपुरा भी पहुंचेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा, ''हम दूषित पेयजल की समस्या के समाधान पर सकारात्मक चर्चा के लिए गांधी की मौजूदगी में बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविदों और राज्य भर के नगर निगम पार्षदों का एक सम्मेलन आयोजित करना चाहते थे, लेकिन हमें प्रशासन ने इस आयोजन की अनुमति नहीं दी। इसलिए हम बाद में यह सम्मेलन

आयोजित करेंगे।''पटवारी ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में 70 प्रतिशत पानी दूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दूषित पेयजल को 'धीमा जहर' करार देते हुए दावा किया कि इससे लोगों की किडनी और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। पटवारी ने संस्कृत की मशहूर कहावत 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' का हवाला देते हुए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा, इंदौर में दूषित पेयजल से कई लोगों की मौत के बावजूद राज्य के मंत्री भव्य आयोजनों में व्यस्त हैं और वे हमें गालियां देकर कह रहे हैं कि हम इस घटना को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं? शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ था। स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप में अब तक 24 लोगों के दम तोड़ने का दावा किया है। मृतकों के आंकड़े को लेकर विरोधाभासी दावों के बीच राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में बृहस्पतिवार को पेश स्थिति रिपोर्ट में भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त प्रकोप के दौरान पांच माह के बालक समेत सात लोगों की मौत का जिक्र किया है। इस बीच, शहर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की एक समिति के किए गए डेथ ऑडिट की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भागीरथपुरा के 15 लोगों की मौत इस प्रकोप से किसी न किसी तरह जुड़ी हो सकती है।

कपिल मिश्रा पर एफआईआर, दिल्ली सरकार जल्द बुला सकती है विधानसभा का विशेष सत्र; पंजाब पुलिस के जवाब पर उठे सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर मामले में दिल्ली सरकार जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। जिसमें आगे की कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब की फोरेंसिक लैब के निदेशक को नोटिस भेजकर कहा कि किस आधार पर आपने दिल्ली विधानसभा की संपत्ति यानी विधानसभा सदन के वीडियो पर अपनी रिपोर्ट दे दी। कहा कि दिल्ली विधानसभा से वीडियो लेना उचित क्यों नहीं समझा। वहीं, दिल्ली विधानसभा के नोटिस पर पंजाब पुलिस के महानिदेशक सहित तीन अधिकारियों ने अपने जवाब दिल्ली विधानसभा को भेज दिए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उनके परिवार में किसी का निधन हो गया है, इसलिए वह अभी उस प्रक्रिया में व्यस्त हैं और जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जालंधर के पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के कारण वह उस आयोजन में व्यस्त है, इसलिए जवाब नहीं दे पाए हैं। वहीं, पंजाब के विशेष महानिदेशक (साइबर क्राइम) ने कहा कि वह रेफर किए गए मामलों पर एफआईआर दर्ज करते हैं, उनका सीधे तौर पर कोई मामला एफआईआर दर्ज करने का नहीं है। दिल्ली विधानसभा इन जवाबों को पंजाब पुलिस की बहानेबाजी मान रही है।

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में बड़े गिरोह का भंडाफोड़, मिला अवैध हथियारों का जखीरा; पांच गिरफ्तार

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस समारोह से पूर्व चाक चौबंद सुरक्षा तैयारी में जुटी दक्षिण-पश्चिम जिला के स्पेशल स्टाफ ने राजधानी में अवैध हथियार बनाने व बेचने वाले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप 20 कट्टा, 12 कारतूस व अन्य सामान बरामद किया है। ये सभी हत्या, गैंगस्टर एक्ट, लूटपाट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। सिंडिकेट लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर, यूपी व हरियाणा के गैंगस्टरों और बदमाशों को अवैध हथियार आपूर्ति कर रहा था। डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तस्करों में उमेद, गांव खेड़ी सकपान, मुजफ्फरनगर, यूपी का रहने वाला है। यह हत्या और गैंगस्टर एक्ट के पहले के दो मामलों में शामिल रहा है। असरफ अली, गांव कैली दौफला, मेरठ का रहने वाला है और हत्या व गैंगस्टर एक्ट के पहले के दो मामलों में शामिल रहा है। बताया गया कि सतीश, गांव कमसरह, मेरठ का रहने वाला है। यह भी हत्या और गैंगस्टर एक्ट के पहले के दो मामलों में शामिल रहा है। भरत, राज नगर पार्ट-दो, पालम का रहने वाला है और हत्या के प्रयास और डकैती के पहले के छह मामलों में शामिल रहा है। इम्तियाज, गांव बगोठेला, सेक्टर-आठ, द्वारका का रहने वाला है और डकैती, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के पहले के आठ मामलों में शामिल रहा है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर अवैध हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मात्रा में मशीनरी और कच्चा माल भी बरामद किया है। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले, अवैध हथियारों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए दक्षिण-पश्चिम जिले की पुलिस ने अवैध हथियारों के निर्माण और सप्लाई में शामिल अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इसके तहत चार तस्करों को सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, इंस्पेक्टर विनय कुमार बालियान की टीम ने राजोकरी टी-प्वाइंट, कापसहेड़ा के पास भरत नाम के एक तस्कर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में इसने अवैध हथियार बनाने वाले एक सिंडिकेट के बारे में बताया और मेरठ के कैली गांव के रहने वाले असरफ अली के शामिल होने के बारे में बताया। वह अवैध हथियार बनाने में सक्रिय रूप से शामिल था। उसने बताया कि असरफ अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहा है और दिल्ली-एनसीआर, यूपी व हरियाणा में सक्रिय अपराधियों और हथियार सप्लाई कर रहा है। उसकी निशानदेही पर कैली गांव में छापामारी कर अवैध हथियार बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ हुआ। वहां से असरफ अली, उमेद और सतीश नाम के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ के बाद इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग सुनसान खेत में एक संगठित तरीके से अवैध हथियार बनाने वाली यूनिट चला रहे थे। वे भारी मशीनरी और कच्चे माल का इस्तेमाल कर कट्टा बना रहे थे। इनके कब्जे से 20 कट्टा, 12 कारतूस, सात लोहे की बैरल, एक लोहे की मशीन, जिसका इस्तेमाल लोहे की प्लेटों को आकार देने के लिए किया जाता है, चार लोहे के ब्लेड वाला एक ग्राइंडर, पांच छेनी, 9 लोहे के मैंड्रिल टूल, 12 वेल्डिंग रॉड, पांच लोहे की रॉड, 18 स्प्रिंग, हथौड़े और स्क्रूड्राइवर, एक हैंड एयर ब्लोअर व आग्नेयास्त्र निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण और कच्चा माल बरामद किया गया।

ईरान में भारतीयों की सुरक्षा

1947 तक भारत के पड़ोसी देश ईरान का इतिहास काफी उथल-पुथल रहा है विशेष कर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की 20वीं सदी में। भारत के साथ इस देश के गहरे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्बन्ध रहे हैं जिसके प्रमाण में इतना ही काफी है कि इसके पूर्व शहंशाह रज़ा पहलवी की पदवी 'आर्य मिहिर' अर्थात आर्यों का सूरज हुआ करती थी। 1954 तक यह देश पूरी तरह लोकतान्त्रिक देश था और इसके लोगों द्वारा चुनावों में चुने गये तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. मोहम्मद मुसद्दिक अपने देश के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध थे परन्तु तब उन्होंने ईरान के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए वहां की तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था जिसके चलते यूरोपीय देशों विशेषकर ब्रिटेन व अमेरिका ने वहां सत्ता बदल को बढ़ावा दिया और शहंशाह रज़ा पहलवी को गद्दीनशीन कर दिया। शहंशाह का शासन 1979 तक चलता रहा मगर इस वर्ष ईरान में इस्लामी क्रान्ति हुई और धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में वहां पुनः सत्ता पलट हुआ। इसमें भी यूरोपीय देशों व अमेरिका के हित बन्धे हुए थे परन्तु 21वीं सदी के शुरू होने के बाद इसमें भी परिवर्तन आना शुरू हुआ और अमेरिकी व यूरोपीय देशों को अपने हित खतरे में लगने लगे। इसकी मूल वजह यही रही कि ईरान अपने बूते पर परमाणु शक्ति बनने की कोशिश करने लगा और अपनी सामरिक ताकत में वृद्धि करने लगा जिससे पश्चिम एशिया का शक्ति सन्तुलन अमेरिका विरोधी धड़े के पक्ष में जा सकता था। ईरान को अपने विकास में 21 वीं सदी में रूस व चीन का साथ मिला जिससे पश्चिमी व अमेरिकी शक्तियों का चिन्तित होना स्वाभाविक था लेकिन अब 2026 चल रहा है और ईरान में 1979 से स्थापित मजहबी शिया इस्लामी शासन के विरुद्ध लोगों में विद्रोह की भावना जागृत हो रही है। इसका मूल कारण यह है कि इस्लामी निज़ाम के चलते लोगों के मूल मानवीय अधिकारों को कुचला गया विशेष कर महिलाओं को ईरान में दोयम दर्जे की नागरिक बना कर रखा गया। अतः इस आज के वातावरण में पूरे ईरान में जन विद्रोह को देख रहे हैं। हालात इतने खराब हो गये हैं कि अभी तक इस्लामी सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में ढाई हजार से अधिक नागरिकों की जान पुलिस बलों द्वारा ले ली गई है। वर्तमान इस्लामी खामेनेई प्रशासन इस जन विद्रोह को अपनी दमनकारी नीतियों से कुचलना चाहता है जिसका विरोध पश्चिमी देश व अमेरिका कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तो साफ कह दिया है कि यदि ईरान ने अपने नागरिकों पर इसी तरह जुल्म ढहाना जारी रखा तो उनका देश ईरान में सैनिक कार्रवाई तक कर सकता है। अमेरिका पूरी दुनिया में मानवीय अधिकारों का अलम्बरदार माना जाता है हालांकि श्री ट्रम्प का इस बारे में सोच व नीति बहुत चुनौती समझी जाती है। हाल ही में उन्होंने जिस तरह दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति को सपत्नीक अपहृत करके वहां सत्ता बदल किया है उससे पूरी दुनिया सहमी हुई है मगर ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि वहां अमेरिका इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता क्योंकि ईरान की सामरिक ताकत बहुत ज्यादा है, खास कर उसके पास अत्याधुनिक मिजाइलों का जखीरा है जो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों को तहस-नहस कर सकता है। पूरे विश्व ने पिछले वर्ष जून महीने में देखा था कि अमेरिका व इजराइल ने मिलकर किस तरह ईरान पर हमला किया था लेकिन यह युद्ध केवल 12 दिन ही चल सका और अमेरिका को युद्ध विराम के लिए सहमत होना पड़ा मगर आज के हालात बदले हुए हैं और ईरान के लोग ही अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं तथा सत्ता बदल चाहते हैं जिसे खामेनेई प्रशासन लोगों पर जुल्म ढहा कर समाप्त करना चाहता है। इससे ईरान की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है क्योंकि श्री ट्रम्प आह्वान कर रहे हैं कि ईरान के लोग अपने हकों के लिए प्रदर्शन जारी रखें उनकी मदद के लिए अमेरिका शीघ्र ही आयेगा। ट्रम्प ने यह भी चेतावनी दे रखी है कि यदि प्रदर्शनकारी नागरिकों को ईरान अपनी अदालती कार्रवाइयों के जरिये फांसी पर चढ़ायेगा तो उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी देश इजराइल है जिसके पास अद्यतन टैक्नोलॉजी के अस्त्र-शस्त्र हैं और जिसे पिछले समय में अरब देशों को युद्ध में हराने का अनुभव भी प्राप्त है लेकिन दूसरी तरफ ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने से बाज नहीं आ रहा है और इसकी न्यायिक प्रणाली के प्रमुख ने कह दिया है कि बागियों के खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमे चलाकर उन्हें माकूल सजा दी जानी चाहिए। इसके चलते ईरान के हालात राजनैतिक व रणनीतिक रूप से बहुत ही अस्थिर व असमंजस भरे होते जा रहे हैं अतः भारत की मोदी सरकार ने ईरान में रह रहे भारत वासियों से कह दिया है कि वे जल्दी से जल्दी ईरान से बाहर आने की कोशिश करें और प्रदर्शन स्थलों से दूर रहें। इस सन्दर्भ में ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास सभी भारतीयों की पूरी मदद करेगा। भारत की सरकार ने पिछले वर्ष 2025 के जून महीने में भी ऐसा ही किया था और ईरान में रह रहे चार हजार से अधिक व इजराइल में रहने वाले सैकड़ों भारतीय नागरिकों को वहां से विशेष विमानों के जरिये निकाला था। ईरान में भारत के विद्यार्थी से लेकर धार्मिक यात्री व व्यापारी तक जाते हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके मूल देश की ही होती है अतः भारत की सरकार ने भविष्य की आशंकाओं को भांपते हुए पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है।

इसका असली कारण यह माना जा रहा है कि ईरान की मौजूदा सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली तक चलाने से बाज नहीं आ रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई को उनका देश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा जिसके चलते ईरान व अमेरिका में सैनिक संघर्ष कभी भी भड़क सकता है। ऐसी परिस्थियों से बचाने के लिए ही मोदी सरकार अपने नागरिकों की रक्षा हेतु यह कदम उठा रही है।

शंख बजा नहीं, महाभारत चालू

जी हां, 5 विधानसभा चुनावों को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा होने में देर है लेकिन चुनाव के अखाड़े के पहलवान पहले से गुत्थमगुत्था होने लगे हैं। ऐसा हो तो रहा है सभी जगह लेकिन बंगाल की लड़ाई तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। शुरुआत में यह हाल है तो आगे चुनाव पूरा होने तक मामला कहां पहुंचेगा, कहना मुश्किल है। चुनाव मई से पहले हो जाएंगे। असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के लिए चुनाव मार्च/अप्रैल में होंगे तो तमिलनाडु और केरल विधानसभाओं के लिए अप्रैल/मई में। निश्चित रूप से चुनाव का ज्यादा शोर मचाने की वजह खास शैली से चुनाव लड़ने वाली भाजपा का मैदान में होना और प्रमुख खिलाड़ी रहना है। और बंगाल में भी ई.डी. जब कोयला घोटाले की जांच का नाम लेकर सीधे तृणमूल की सलाहकार कंपनी के दफ्तर से फाइलें उठाने लगी तो पुलिस बल समेत आकर खुद ममता बनर्जी ने वे फाइलें छीन लीं। अब कौन गलत कौन सही की लड़ाई सड़क पर और सुप्रीम कोर्ट में चलने लगी है। चुनाव के पहले उसका निपटारा भी संभव नहीं लगता।

अभी की स्थिति में भाजपा एक राज्य में शासन में है और दूसरे में काफी पिछड़ कर मुख्य विपक्ष है। पर एक राज्य, पुडुचेरी में उसने जिस तरह सरकार बना ली, वह उसकी राजनीतिक लड़ाई लड़ने का तरीका है। अगर चुनावों को लेकर अभी से गरमाहट आ गई है तो यह भी भाजपा के चुनाव लड़ने का तरीका है जो नगर पालिका चुनाव तक को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा से जोड़ देता है। मुश्किल यह है कि 3 अन्य राज्यों में वह कमजोर है तो बंगाल में ममता बनर्जी भी लड़ाई को जुझारू तरीके से ही लड़ने को तैयार हैं। 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को मुख्य टक्कर देने के बाद भाजपा को लग रहा है कि 15 साल के ममता राज से लोगों की जो नाराजगी बढ़ी है, उसका लाभ लेकर वह इस बार बंगाल का किला फतह कर सकती है। पर उसकी मुश्किल यह है कि उसके पक्ष में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो उभार आने लगा था, वह उतार पर आता दिखने लगा है। उसका वोट प्रतिशत गिरा है। साथ ही उसके सांसद और विधायक भी कम चुने गए हैं। दल बदल में भी अब मौकापरस्त या किसी दबाव में उसकी तरफ आने वालों की रफ्तार कम हुई है। इसके साथ ही वहां के लगभग एक-चौथाई मुसलमान मतदाता भी अब पूरी तरह तृणमूल के साथ आ गए हैं। बंगाल में समाज सुधार आंदोलनों के चलते जाति की गोलबंदी कम है और समाज पर प्रभावी भद्रलोक में भाजपा की घुसपैठ नहीं है। भाजपा की मुश्किल कांग्रेस और वाम दलों के एकदम पस्त होने से भी बढ़ी है, जिनका वोट उसकी तरफ आने से ज्यादा तृणमूल की तरफ गया है। असम में भी भाजपा की परेशानी 10 साल शासन करने और नागरिकता या घुसपैठ जैसे किसी मुद्दे पर ज्यादा कुछ न कर पाने से जुड़ी है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को असम का चार्ज देकर लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस ने जब से मौलाना बदरुद्दीन वाली मुसलमानों की पार्टी से रिश्ता तोड़ा है,

उसे मुसलमानों का भरपूर वोट तो मिला ही, भाजपा के लिए उस पर हमला करना और चुनाव को हिंदू-मुसलमान बनाना मुश्किल हुआ है। इस बार भाजपा को ज्यादा परेशानी अहोम सरबानंद सोनोवाल को हटाकर हेमंत बिस्व सरमा को मुख्यमंत्री बनाने से भी जुड़ी है। सरमा प्रशासनिक रूप से कुशल हैं पर असमी समाज में शासक रहे अहोम समाज को सत्ता जाने का मलाल है। असम में बहुत किस्म की अस्मिताएं/पहचान काम करती हैं लेकिन नागरिकता, सी.ए.ए., पॉपुलेशन रजिस्टर, जनगणना और गहन मतदाता सर्वेक्षण जैसे किसी भी सवाल पर स्पष्ट फैसला न लेना और कोई नतीजा न देना भाजपा को परेशान करेगा। तमिलनाडु के चुनाव में भाजपा ही नहीं, पूरा विपक्ष अभी पहले से कमजोर लग रहा है। अन्नाद्रमुक में टूट और भाजपा का उससे छिटकना ही नहीं हुआ है, भाजपा कोइरियों वाली पार्टी पी.एम.के. का दोफाड़ होने के बाद अंबुमणि धड़े के साथ हाथ मिलाने और अभिनेता विजयकांत की गवाहियों वाली पार्टी को साथ लेने के लिए प्रयास कर रही है। अन्नाद्रमुक से निकले थेवर नेता पनीरसेल्वम और दिनकरण भी अभी ठिकाना नहीं पा सके हैं। कभी विजयकांत को साथ लेकर कांग्रेस तीसरा मोर्चा बनाना चाहती है, कभी द्रमुक सरकार में मंत्री पद। उधर द्रमुक, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन हर तरह से मजबूत और एकजुट दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि विपक्षी गठजोड़ बन भी जाए तो एम.के. स्टालिन को हराने लायक दम जुटाना मुमकिन नहीं। केरल को लेकर भाजपा जरूर इस बार उत्साहित है, हालांकि वहां भी लोकसभा चुनाव में वह शून्य पर ही आ गई थी। लेकिन उसे ठीक-ठाक वोट मिले हैं और अभी त्रिवेंद्रम की स्थानीय सरकार पर उसके कब्जे से उसका उत्साह बढ़ा है। पर बहुत साफ जातिगत और सांप्रदायिक गोलबंदी वाले केरल समाज में भाजपा कुल मिलाकर हिन्दू नायरों और कुछ असंबद्ध युवकों को ही आकर्षित कर पाई है। और यह वोट जितना बढ़ेगा, 10 साल से शासन कर रही वाम मोर्चा सरकार की परेशानियां बढ़ेंगी क्योंकि भाजपा के लिए ईसाई और मुसलमान वोट पाना संभव नहीं है। यह स्थिति कांग्रेस के लिए अच्छी बन जाती है, जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, राहुल और प्रियंका गांधी के वहां से चुनाव लड़ने के चलते आया उत्साह भर है। 20 लाख से कम आबादी वाले पुडुचेरी की आबादी का संतुलन बहुत नाजुक है और जिस तरह पिछली बार भाजपा ने वहां मनोनयन वाले 3 विधायकों और राज्यपाल के सहारे सरकार बना ली, उससे नाराजगी है। इसलिए सभी 5 विधानसभा चुनावी राज्यों में भाजपा अपने लिए जश्न मनाने की स्थिति कैसे बना पाती है, यह देखना होगा।

सम्पादकीय...

मैं राजेश खन्ना बनूंगा

नौकरी डॉट कॉम कहिए, जीवनसाथी डॉट कॉम या पॉलिसीबाजार का जिक्र कीजिए, लगभग हर कोई तुरंत समझ जाता है कि बात किसकी हो रही है लेकिन जैसे ही संजीव बिखचंदानी का नाम लिया जाता है, बहुत से लोग थोड़े ठिठक जाते हैं। कौन हैं वे? नाम जाना-पहचाना लगता है, पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं। वे किस लिए जाने जाते हैं? ये सवाल स्वाभाविक हैं, क्योंकि आज के दौर में ब्रांड अपने निर्माताओं से कहीं बड़े हो चुके हैं। यह स्थिति अपने आप में खुशी और गर्व दोनों का विषय है। ठीक वैसे ही जैसे किसी माता-पिता के लिए यह संतोष की बात होती है कि उनका बच्चा इस तरह आगे बढ़े कि लोग उसे माता-पिता की पहचान से नहीं, बल्कि माता-पिता को उसकी पहचान से जानें। संजीव बिखचंदानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आज वे अपने ब्रांड्स के माध्यम से अधिक पहचाने जाते हैं, न कि उनके ब्रांड्स उनके नाम से। हालांकि कॉरपोरेट, बिजनेस और डॉट-कॉम की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए संजीव बिखचंदानी कोई अनजान नाम नहीं, बल्कि एक जाना-पहचाना व्यक्तित्व हैं। डॉट-कॉम की दुनिया में क्रांति लाने वाले संजीव बिखचंदानी को आज भले ही 'स्टार्ट-अप्स के जनक' के रूप में जाना जाता हो लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस शब्द से, कम से कम दुनिया के इस हिस्से में, बहुत कम लोग परिचित थे। दिलचस्प यह है कि अपने शुरुआती दौर में बिखचंदानी स्वयं ई-मेल जैसी अवधारणा से भी अनजान थे। भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित एक प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने एक स्टॉल संचालक से पूछा था- ई-मेल क्या होता है? साल 1996 में बिखचंदानी ने पहली बार इंटरनेट को देखा। वे बताते हैं, एक प्रदर्शनी में मैंने '222' लिखा हुआ एक छोटा सा स्टॉल देखा। मैंने स्टॉल वाले से पूछा कि यह क्या है, तो उसने कहा- ई-मेल। जब उसने विस्तार से समझाया तो बिखचंदानी की पहली प्रतिक्रिया थी, यह तो फेल हो जाएगा। उनका तर्क सीधा था, जब बहुत कम लोगों के पास ई-मेल है तो मेल भेजेंगे किसे? यह ऐसा है जैसे दुनिया में सिर्फ एक ही टेलीफोन हो तो बात किससे करेंगे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्टॉल संचालक ने उन्हें दोबारा बुलाकर कहा इंटरनेट भी है। बिखचंदानी बताते हैं कि उन्होंने इंटरनेट का नाम पहली बार वहीं सुना। जब उस व्यक्ति ने समझाया कि इंटरनेट के जरिये आप अपने घर या दफ्तर से लॉग-इन कर दुनिया भर की हजारों कंपनियों में संग्रहित जानकारियों तक पहुंच सकते हैं तो बात कुछ और ही हो गई। उसने याहू खोलकर पूछा क्या सर्च करना है? बिखचंदानी ने कहा- इंडिया। क्लिक करते ही ढेरों वेबपेज सामने आ गए। यहीं बिखचंदानी को वह विचार सूझा जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। वे कहते हैं, तभी मुझे लगा कि क्यों न देश भर के अखबारों से नौकरियों के विज्ञापन लेकर उन्हें इंटरनेट पर डाल दिया जाए और देखा जाए कि क्या होता है। इसके बाद, जैसा कि कहा जाता है, इतिहास बनता चला गया। इस विचार की पृष्ठभूमि कहीं और भी तैयार हो रही थी। बिखचंदानी को याद है कि उनके दफ्तर में युवा कर्मचारी एक मैगजीन को हमेशा पीछे के पन्नों से पढ़ते थे। वे समाचार पत्रों को छोड़ सीधे विज्ञापनों पर जाते थे। तब बिजनेस इंडिया के पिछले पन्नों में 30-40 पेज सिर्फ नियुक्ति विज्ञापनों के होते थे। लोग लेख पढ़ें या न पढ़ें, विज्ञापन जरूर देखते थे।

हाईकोर्ट ने कहा- झूठी FIR कराने वालों पर पुलिस को करना होगा केस

हाईकोर्ट ने कहा जांच-अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सूचना देने वाले के खिलाफ झूठी गवाही और गुमराह करने पर FIR दर्ज कराए.

वरिष्ठ संवाददाता

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठे मुकदमों और पुलिस तंत्र के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि पुलिस जांच में पाया जाता है कि एफआईआर झूठी सूचना के आधार पर दर्ज कराई गई थी, तो विवेचना अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सूचना देने वाले के खिलाफ झूठी गवाही और गुमराह करने का लिखित परिवाद दर्ज कराए, यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने दिया है.

यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad) का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आदेश है, जिसे न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी (Hon'ble Praveen Kumar Giri, J.) ने 14 जनवरी, 2026 को पारित किया है।

यह आदेश उम्मे फरवा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (mme Farva vs. State of U.P. and Another) के मामले में आया है, जो फर्जी मुकदमों (Fake Cases) और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करता है।

इस आदेश के मुख्य बिंदु और विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है-

1. मामले का संदर्भ (Conte&t)

यह याचिका BNSS की धारा 528 (जो पुरानी छ्ह्र्क्कष्ट की धारा 482 के समान है) के तहत दायर की गई थी। इसमें आवेदक ने अपने खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे और मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान (Cognizance) को चुनौती दी थी।

2. पुलिस और जांच अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश

न्यायालय ने पाया कि कई मामलों में पुलिस बिना उचित जांच के या गलत तथ्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर देती है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि-

धारा 212 और 217 BNS (पुरानी IPC की धारा 177 और 182)- यदि कोई व्यक्ति पुलिस को झूठी सूचना देता है, तो पुलिस अधिकारी की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करे।

अधिकारियों की जवाबदेही- यदि जांच अधिकारी (IO), थाना प्रभारी (SHO) या क्षेत्राधिकारी (CO) और लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ धारा 199(b) BNS (पुरानी IPC की धारा 166(b)) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

3. अदालती अवमानना (Contempt of Court) की चेतावनी

आदेश के पैरा 50 में कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है-

* यदि पुलिस अधिकारी या न्यायिक अधिकारी इस आदेश का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं, तो इसे अवमानना (Contempt of Court) माना जाएगा।
* पीड़ित व्यक्ति अवमानना की कार्यवाही के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

4. 60 दिनों की समय सीमा

अदालत ने पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने और कानूनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए इस आदेश की तारीख (14 जनवरी 2026) से 60 दिनों का समय दिया है।

5. न्यायिक अधिकारियों के लिए संदेश

अदालत ने संबंधित मजिस्ट्रेट के स्पष्टीकरण को कुछ हद तक संतोषजनक पाया और कहा कि इस आदेश की टिप्पणियों का उनके करियर या सेवा रिकॉर्ड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में सतर्क रहने का संकेत दिया।

निष्कर्ष और महत्व-

यह आदेश उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। अब पुलिस केवल चार्जशीट दाखिल करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती; यदि शिकायत झूठी पाई जाती है, तो पुलिस को शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी, अन्यथा पुलिस अधिकारी खुद अपराधी माने जाएंगे।

संक्षेप में यह आदेश %फर्जी केस% कल्चर को खत्म करने और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पुलिस अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई- कोर्ट ने कहा कि यदि विवेचक जांच के बाद यह पाता है कि आरोप झूठे थे और क्लोजर रिपोर्ट लगाता है, तो उसे सूचना देने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 और 217 (आईपीसी की धारा 177 और 182 के समतुल्य) के तहत लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी. कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 (बी) के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

60 दिन में आदेश का पालन करना है- कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राज सिंह (1998) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि झूठी सूचना के अपराधों में कोर्ट लोक सेवक की लिखित शिकायत के बिना संज्ञान नहीं ले सकता, इसलिए पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करना अनिवार्य है. कोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और न्यायिक अधिकारियों को 60 दिन के भीतर जिन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, उनमें

झूठी सूचना पर कार्रवाई अनिवार्य: जब भी पुलिस किसी मामले में यह कहते हुए अंतिम रिपोर्ट लगाती है कि आरोप झूठे या भ्रामक थे, तो पुलिस को अनिवार्य रूप से सूचना देने वाले और गवाहों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 215 (1) के तहत लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी.

मजिस्ट्रेट की भूमिका: मजिस्ट्रेट ऐसी अंतिम रिपोर्ट को तब तक स्वीकार न करें जब तक उसके साथ झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ लिखित शिकायत न हो. यदि प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की जाती है, तो पुलिस की शिकायत पर कार्यवाही तब तक रुकी रहेगी जब तक प्रोटेस्ट पिटीशन पर निर्णय नहीं हो जाता.

अवमानना की चेतावनी- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का पालन न करना अदालत की अवमानना माना जाएगा.

इस मामले में न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने यह भी साफ किया कि असंज्ञेय अपराधों में पुलिस की रिपोर्ट को स्टेट केस नहीं, बल्कि परिवाद माना जाना चाहिए. इसी के साथ कोर्ट ने अलीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें असंज्ञेय मामले में पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञेय अपराध की तरह संज्ञान लिया गया था.

मामला वैवाहिक विवाद का है- पति ने अपनी पत्नी (याची) के खिलाफ क्वार्सी थाने में आईपीसी की धारा 504 और 507 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी. पति का आरोप था कि उसकी पत्नी, जो कोरिया में किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है, फेसबुक के जरिए उसे और उसकी बेटी को बदनाम कर रही है और भारत लौटने पर जान से मारने की धमकी दी है.

पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई- पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपों को झूठा पाते हुए अंतिम रिपोर्ट लगा दी. इसके बाद पति ने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की तो अलीगढ़ के सीजेएम ने प्रोटेस्ट पिटीशन स्वीकार करते हुए अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी और सीआरपीसी की धारा 190 (1)(बी) के तहत मामले का संज्ञान लेते हुए इसे स्टेट केस के रूप में चलाने का आदेश दिया.

स्टेट केस के रूप में दर्ज करना कानूनन गलत- पत्नी ने याची (पत्नी) के वकील ने तर्क दिया कि वैवाहिक कलह के कारण याची को दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगाई थी और अपराध असंज्ञेय प्रकृति के थे इसलिए मजिस्ट्रेट का इसे स्टेट केस के रूप में दर्ज करना कानूनन गलत था. पति और सरकारी वकील ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने जांच के दौरान एकत्र सबूतों का सही मूल्यांकन किया है और आदेश में कोई अवैधता नहीं है.

पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा- कोर्ट ने पाया कि आईपीसी की धारा 504 और 507 असंज्ञेय और जमानती अपराध हैं. कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 2(डी) के स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा और पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया.

HC ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा- असंज्ञेय अपराध को संज्ञेय अपराध की तरह माना. सीजेएम को इस मामले को परिवाद के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए था. इसी के साथ कोर्ट ने अलीगढ़ सीजेएम के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट अब कानून के अनुसार और आरोपी को सुनवाई का मौका देते हुए तीन महीने के भीतर नया आदेश

पीड़ितों का शास्त्र न बन जाए उमर-शरजील की हिरासत

छह साल पहले राजधानी दिल्ली के उत्तरी-पूर्वी हिस्से के जाफराबाद और मौजपुर में हुए दंगों पर राजनीति थम नहीं रही है। राजनीति तब भी खूब हुई, जब 23 फरवरी 26 फरवरी 2020 के बीच हुए दंगों का घाव बिल्कुल हरा था। इस बार इन दंगों पर राजनीति की वजह पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से आया एक आदेश है, जिसमें इन दंगों के पांच आरोपियों गुलफिशां फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी गई है। इस आदेश को लेकर राजनीति ही नहीं हो रही, प्रकारांतर से देश की सबसे बड़ी अदालत भी निशाने पर है। सर्वोच्च अदालत ने इन दंगों के आरोपी शरजील इमाम उमर खालिद को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर इन दोनों आरोपियों के पक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई। मनमोहन सिंह की सत्ता और कांग्रेस के आंख के तारे रहे जेएनयू के पूर्व छात्र रहे एक बड़े पत्रकार ने इन दोनों आरोपियों को देश का प्रखर बुद्धिजीवी बताते हुए उन्हें जमानत ना दिए जाने पर आश्चर्य जताया। वामपंथी वैचारिकी की एक खासियत है। वह अपने पक्ष में अकादमिक तर्क गढ़ने में माहिर रही है। अपने लिहाज के तथ्यों को चुनकर उसके हिसाब से वह तर्क गढ़ने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही अपनी वैचारिकी के लोगों को पीड़ित दिखाने में वह हमेशा आगे रहती रही है। शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में वामपंथी वैचारिकी उसी तरह से उमड़ पड़ी है। वह दोनों के बारे में यह राय बनाने की भरपूर और प्रभावी कोशिश कर रही है कि दोनों दंगाई नहीं, दंगे के शातिर षड्यंत्रकारी नहीं, बल्कि वे प्रखर बुद्धिजीवी हैं। वामपंथी वैचारिकी यह साबित करने की भी कोशिश कर रही है कि दोनों चूंकि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से हैं, और चूंकि केंद्र में हिंदुत्ववादी सत्ता है। इसलिए अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों को दबाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात यह विमर्श खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्ववादी सत्ता के इशारे पर अदालत मुस्लिम समुदाय के निर्दोष बुद्धिजीवियों को बलि का बकरा बना रही है। यह विमर्श खड़ा करके वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात दरअसल दंगाइयों को पीड़ित के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प यह है कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत को नकारने के लिए जहां सर्वोच्च न्यायालय को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं बाकी पांच आरोपियों को जमानत दिए जाने के आदेश को जबरदस्ती नेपथ्य में धकेलने की कोशिश की जा रही है। दो लोगों को जमानत ना मिलने को, पांच लोगों को जमानत मिलने की प्रक्रिया के सामने पक्षपाती दिखाया जा रहा है। पांच आरोपियों को मिली जमानत को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा करके सर्वोच्च अदालत ने कोई एहसान नहीं किया है। वामपंथी वैचारिकी के इस विमर्श का पूरा मकसद यह भुलाना है कि 2020 के दिल्ली दंगे हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं थे। इस विमर्श का लक्ष्य यह भी भुलाना है कि इन दंगों में अधिसंख्य हिंदू समुदाय के लोग मारे गए थे। इस विमर्श का यह भी मकसद है कि इन दंगों के दौरान आईबी के मासूम अधिकारी अंकित शर्मा की हुई हत्या को सामान्य अपराध दिखाने की कोशिश हो रही है। इन दंगों में आधिकारिक रूप से 53 लोग मारे गए थे। दंगा खत्म होने के बाद कई लाशें नाले में बहती मिलीं। जिस तरह उस दौरान दंगे के एक आरोपी आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन के घर पत्थर, हथियार और बड़ी-सी गुलेल मिली, उससे तो यही साबित होता है कि दिल्ली के ये दंगे हिंदू समाज को सबक सिखाने की मुस्लिम समाज के कुछ दंगाइयों की कोशिश थी। इन दंगों की टाइमिंग को भी भुलाना आसान नहीं है। जब ये दंगे हुए थे, उसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का भारत दौरा हुआ था। इन दंगों के जरिए कोशिश यह भी की गई थी कि दंगा के षड्यंत्रकारियों का मकसद ट्रंप की भारत यात्रा को निरस्त कराना, भारतीय राज व्यवस्था को बदनाम करना और इसके जरिए भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाना था। इसमें किंचित वे कामयाब भी हुए। शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में उठतीं आवाजों का प्रतिकार भी जरूरी है। इन आवाजों की पोल खोलना भी जरूरी है। राष्ट्रवादी धारा के प्रबुद्धजन वामपंथी विमर्श के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन जिस तरह कभी वामपंथी वैचारिकी के अगुआओं को देश की मौजूदा व्यवस्था में राजकीय तवज्जो मिल रहा है, उससे प्रखर राष्ट्रवादी वैचारिकी किंचित परेशान भी है और दुखी भी। इसलिए जैसा इस वामपंथी विमर्श का प्रतिकार होना चाहिए, उस स्तर का प्रतिकार नहीं हो पा रहा है। यह तो भला हो कि हिंदुत्ववादी मानस इन दिनों बेहद सचेत हो चुका है। निश्चित तौर पर इसकी वजह मुस्लिम तुष्टिकरण की हकीकत का सामने आना तो है ही, केंद्रीय सत्ता में मोदी की अगुआई में हिंदुत्ववादी ताकतों का प्रभावी बनना भी है। दिल्ली दंगों को लेकर नए विमर्श गढ़ने की कोशिशें होती रहेंगी। जरूरत यह है कि इसका लगातार उचित प्रतिकार तो होते ही रहे, हिंदुत्व विरोधी नैरेटिव के खिलाफ आक्रामक राष्ट्रवादी विमर्श लगातार उठता रहे। इसी अंदाज में होना यह चाहिए कि दिल्ली दंगों को लेकर बार-बार यह कहा जाना चाहिए कि ये हिंदुओं के खिलाफ खुराफाती और शांति विरोधी मुस्लिम सिरफिरों के सुनियोजित अपराध थे। जिसमें 53 लोगों की मौत हुई। इनमें ज्यादातर हिंदू थे। दो सौ से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भी बताने की कोशिश होनी चाहिए कि घायलों में भी ज्यादातर हिंदू ही थे। इसकी भी बार-बार चर्चा होनी चाहिए कि इन दंगों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय की ही दुकानों और हिंदू समुदाय के ही मकानों को लक्ष्य बनाकर नुकसान पहुंचाया गया। यह भी बताने की कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए कि इन दंगों का एक मकसद तत्कालीन नागरिकता संबंधी कानून में संसद द्वारा किया गया संशोधन भी था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी दुष्प्रचार भी था। लगातार ऐसा जवाबी विमर्श खड़ा होता रहा तो मुस्लिम समुदाय के शांति विरोधी और अपराधी और दंगाई समर्थक वर्ग की मंशा का खुलासा करना आसान होगा। लगातार जारी ऐसे विमर्श की वजह से हिंदुत्व विरोधी ताकतें जहां एक्सपोज होंगी, वहीं उनके खिलाफ आम मानस उठ खड़ा होगा। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाली राजनीतिक धाराएं भी इससे एक्सपोज होंगी। इस प्रक्रिया के लगातार जारी रहने के चलते एक दौर ऐसा भी आएगा, जब छद्म विमर्शकारों के सामने सच को पूरी हकीकत के साथ स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल यह जान लेना चाहिए कि जिन पांच आरोपियों को सर्वोच्च अदालत ने जमानत दी है, उन्हें दो-दो लाख के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। सर्वोच्च अदालत ने इन आरोपियों की जमानत मंजूर करते वक्त बारह कड़ी शर्तें लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि ये आरोपी किसी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते और पोस्टर नहीं बांट सकते। अदालत ने ताकीद की है कि वे किसी भी कीमत पर अपने खिलाफ चल रहे मामले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि जमानत पर बाहर आए ये पांचों आरोपी लगातार पाडकास्ट कर रहे हैं, समाचार माध्यमों को साक्षात्कार दे रहे हैं। इसके जरिए वे जेल जीवन की विद्रूपताओं को उजागर तो कर ही रहे हैं, राजव्यवस्था को पक्षपाती साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जमानत पाए आरोपियों के इन कार्यों का मकसद असल में हिंदुत्ववादी विचारधारा, भारतीय राज व्यवस्था और न्यायव्यवस्था को कठघरे में खड़ा करना है।

राष्ट्रवादी ताकतों को अगर इन ताकतों पर पार पाना है तो वामपंथी वैचारिकी के खिलाफ तार्किक हमला करना होगा, भावनात्मक नहीं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

ओडीओपी योजना के तहत 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

पडरौना, कुशीनगर।

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र कुशीनगर के तत्वावधान में रामकोला स्थित एक मैरेज लॉन में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में विधायक रामकोला विनय प्रकाश, विधायक पडरौना मनीष जायसवाल तथा भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने फीता काटकर और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर विधायक रामकोला विनय प्रकाश गोंड ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं और अपने साथ कार्य करने वाले लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएं। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण का भरपूर लाभ उठाने और सफल उद्यमी बनने की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान विधायक द्वारा 10 लाभार्थियों को स्टडी किट का वितरण भी किया गया। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा प्रायोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में केले के उत्पाद से जुड़े 350 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन यू.पी. इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (यूपीकॉन) द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे लोकल फॉर वोकल की अवधारणा को मजबूती मिल सके। कार्यक्रम का संचालन आशुतोष सिंह व गायक अनीष सोनी द्वारा किया गया।

श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ

बनकटाशिव सल्हपुर में वैदिक विधि-विधान से ध्वज स्थापना व भूमिपूजन संपन्न

भटनी देवरिया।

बनकटाशिव सल्हपुर में आयोजित श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रथम चरण दिनांक 16 जनवरी 2026 को श्रद्धा एवं वैदिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर महायज्ञ स्थल पर पवित्र ध्वज स्थापना एवं भूमिपूजन का आयोजन विधिवत रूप से किया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। ध्वज स्थापना एवं भूमिपूजन का पावन अनुष्ठान मुख्य यज्ञाचार्य श्री रंगनाथ त्रिपाठी के आचार्यत्व में, यजमान डॉ. नंदकिशोर तिवारी जी सपत्नीक तथा महायज्ञ के आयोजक प्रभात कुमार राय के कर-कमलों से बौद्धिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। मंत्रोच्चार और विधि-विधान के बीच उपस्थित श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। आयोजन समिति द्वारा जानकारी दी गई कि इस महोत्सव के अंतर्गत 15 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक अमृतमयी श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसका वाचन कथा व्यास पूज्या लक्ष्मी प्रिया जी द्वारा किया जाएगा। वहीं भजन संध्या में देश के विभिन्न प्रांतों से सुप्रसिद्ध भजन कलाकार सहभागिता करेंगे, जिनमें श्री राजीव सिंह भागलपुर, बिहार, श्रीमती स्वाति मिश्रा मुंबई, महाराष्ट्र, श्री सुधारी व्यास (इंदौर, मध्यप्रदेश), श्री ध्रुव शर्मा एवं स्वर्ण श्री जी वृंदावन-मथुरा, श्री कुमार सत्यम (मुंबई, महाराष्ट्र), सुश्री करीना पाण्डेय एवं सुश्री शोभिता पाण्डेय पटना, बिहार शामिल हैं। ध्वज स्थापना एवं भूमिपूजन के इस पावन अवसर पर क्षेत्र के अनेक सम्मानित नागरिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से समाजसेवी उमाशंकर राय, राजेश राय, नीलेश्वर राय, डॉ सुदामा यादव, डॉ इंद्रदेव राय, डॉ राजेश्वर शाही, डॉ अमित राय, इंजीनियर जितेंद्र यादव, पप्पू पाण्डेय, छोटू तिवारी, विद्यासागर यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन मौजूद रहे। आयोजन समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से इस महायज्ञ एवं प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की है।

हस्तशिल्प प्रदर्शनी में क्रोशिया उत्पाद बने ग्राहकों की पहली पसंद

कसया, कुशीनगर।

बुद्ध स्थली कुशीनगर स्थित बिरला धर्मशाला में आयोजित 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी में क्रोशिया उत्पाद ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। आकर्षक डिज़ाइन, बेहतरीन गुणवत्ता और बारीक हस्तकला के कारण क्रोशिया उत्पादों के स्टॉल पर खरीदारी और जानकारी लेने के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है। प्रदर्शनी के नौवें दिन शुक्रवार को जैसे ही धूप निकली, महिलाएं, बच्चियां और उनके अभिभावक बड़ी संख्या में पहुंचे।

उन्होंने कपड़ों और धागों से तैयार क्रोशिया कला के विभिन्न उत्पादों की सजावट, डिज़ाइन और निर्माण प्रक्रिया की जानकारी ली और जमकर खरीदारी की। स्टॉल संचालिका एवं हस्तशिल्पी बबिता ने बताया कि क्रोशिया एक महत्वपूर्ण हस्तकला है, जिसमें कारीगरों की मेहनत और रचनात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा प्रायोजित है, जिससे कारीगरों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन का बेहतर मंच मिल रहा है।

हस्तशिल्प और क्रोशिया से जुड़े हैं 500 क्लस्टर : देश दीपक दूबे

भारतीय राष्ट्रीय समाज पार्टी के देवरिया जिले की ब्राह्मण इकाई के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी पंडित अतुल पांडेय, नवीन और सरफराज ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और हस्तशिल्प की सराहना की। प्रदर्शनी निदेशक देश दीपक दूबे ने बताया कि हस्तशिल्प और क्रोशिया से जुड़े लगभग 500 क्लस्टर देशभर में कार्यरत हैं, जिन्हें तकनीकी सहायता और टूल किट उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ-साथ उनकी कला को व्यापक पहचान दिलाने में सहायक साबित हो रही हैं।

पांच ग्राम पंचायतों में खुले लीगल एड क्लीनिक, गांव में ही मिलेगा न्याय का सहारा

देवरिया।

अब न्याय के लिए तहसील और अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भाटपाररानी तहसील क्षेत्र की पांच ग्राम पंचायतों में विधिक सहायता केंद्र (लीगल एड क्लीनिक) की शुरुआत कर दी है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर ही जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक परामर्श और अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में शुक्रवार को ग्राम पंचायत भिंगारी, खामपार, बलुआ अफगान, निशानियां पैकोली और सरया में लीगल एड क्लीनिक का उद्घाटन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार तिवारी तथा ग्राम न्यायालय भाटपाररानी के न्यायाधिकारी सिद्धी जय प्रकाश द्वारा किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार

भाटपाररानी संजय तिवारी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि विधिक सहायता केंद्रों का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से वृद्धजन, महिलाएं, विधवाएं, बच्चे और कमजोर वर्ग अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और शोषण के मामलों में समय पर मदद प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ही छोटे-मोटे विवाद, पारिवारिक झगड़े और सामाजिक मतभेदों का समाधान संवाद और कानूनी मार्गदर्शन के जरिए संभव होगा, जिससे न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ भी कम होगा। साथ ही उन्होंने शासन द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देते हुए आमजन से इनका लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर ई-लॉ कमेटी और असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी के माध्यम से महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का हिंदी अनुवाद कराया गया है, जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। नायब तहसीलदार संजय तिवारी ने ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि विधिक जागरूकता से ही सामाजिक न्याय की स्थापना संभव है। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, पराविधिक स्वयंसेवक, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

मनोज कुमार तिवारी बोले— विधिक सहायता केंद्रों से आमजन के अधिकार होंगे सुरक्षित

तेंदुआ जाल से निकलकर बेकाबू, वनकर्मियों पर हमला; तीन घायल, ड्रोन से निगरानी जारी

नेबुआ नौरंगिया/कुशीनगर।

कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में शुक्रवार को गन्ने के खेत में फंसा एक तेंदुआ जाल फटने के बाद बेकाबू हो गया। रेस्क्यू के दौरान तेंदुए ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घटना सिसवा गोपाल गांव के नहर पश्चिमी पटरी स्थित रेगुलेटर से करीब 300 मीटर की दूरी पर हुई। गांव प्रधान के भाई इंद्रेश गन्ना काटने खेत जा रहे थे, तभी उनकी नजर राजेश लाल श्रीवास्तव के खेत में तार में फंसे तेंदुए पर पड़ी। शोर मचाने पर आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर महराजगंज और कुशीनगर की संयुक्त वन विभाग टीम पहुंची। रेस्क्यू के लिए डाला गया जाल फटा हुआ था। जैसे ही तार काटा गया, तेंदुए ने खुद को ढीला पाकर वन दरोगा पर हमला कर दिया। इसके बाद एक अन्य वनकर्मी को मुंह में दबोचकर गन्ने के खेत की ओर भागने लगा, तभी ग्रामीण कृष्णनंदन कुमार ने लाठी से वार कर उसकी जान बचाई। ग्रामीणों का आरोप है कि फटा जाल और संसाधनों की कमी के कारण तेंदुआ भाग निकला।

भीड़ और शोर-शराबे से स्थिति और बिगड़ी। इसी अफरा-तफरी में तेंदुआ खेतों में छिप गया। ग्रामीण अंगद सहित कई लोग घायल हुए हैं। महराजगंज के वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हेड अरशद हुसैन भी हमले में घायल बताए गए हैं।

डीएफओ पहुंचे, ड्रोन से निगरानी

तेंदुए के रेस्क्यू के लिए कुशीनगर के डीएफओ वरुण कुमार पांचों रेंज के 50 से अधिक वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। छह जाल लगाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस भी तैनात की गई है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौके से दूर रहें और तेंदुए को उकसाने की कोशिश न करें। वन रेंजर अमृता सिंह ने बताया कि टीम 5 जनवरी से क्षेत्र में कैंप कर रही थी और सतत निगरानी जारी थी। डीएफओ अरुण सिंह के अनुसार, गोरखपुर चिड़ियाघर की टीम भी बुला ली गई है। तेंदुआ अभी इसी इलाके में है और उसे जल्द सुरक्षित पकड़ लिया जाएगा। लगातार घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खेतों में गन्ने की कटाई-छिलाई चल रही थी, ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है।

सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा, खराब प्रदर्शन पर जिलाधिकारी सख्त

कुशीनगर। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यक्रमों की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कम रैंकिंग वाले विभागों की एक-एक कर गहन समीक्षा की गई, जिसमें पीएम सूर्यघर योजना, आईसीडीएस, एनआरएलएम, जल जीवन मिशन, फैमिली आईडी, छात्रवृत्ति योजनाएं, मुख्यमंत्री युवा कल्याण योजना तथा नई सड़कों के निर्माण कार्य प्रमुख रूप से शामिल रहे। पीएम सूर्यघर योजना में अत्यंत धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि जनवरी और फरवरी माह में 500-500 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित कर लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। फैमिली आईडी योजना की समीक्षा के दौरान विगत 15 दिनों से शून्य प्रगति वाले चार खण्ड विकास अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि सुधार न होने पर शो-कॉज नोटिस जारी की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आईसीडीएस, एनआरएलएम और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं सीधे आमजन से जुड़ी हैं, इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रवृत्ति योजनाओं में पात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन और समयबद्ध डाटा अपलोड पर भी विशेष जोर दिया गया। नई सड़कों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने तथा मुख्यमंत्री युवा कल्याण योजना के तहत युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग सुधारना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लापरवाही, उदासीनता या गलत रिपोर्टिंग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। अंत में उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026- छठे दिन रीडिंग इंडिया संवाद और सेना दिवस रहे मुख्य आकर्षण

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पठन संस्कृति के निर्माण से लेकर सैन्य बलिदान को नमन करने तक, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के छठे दिन विचारों, इतिहास और राष्ट्रबोध का सार्थक संगम नजर आया. पठन एवं पुस्तकालयों के उन्नयन पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय नेतृत्व संवाद रीडिंग इंडिया संवाद 2026 का शुभारंभ 15 जनवरी 2026 को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा आयोजित यह संवाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तथा विकसित भारत@2047 की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप भारत के पठन, पुस्तकालय और ज्ञान तक पहुंच के पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्रीय समन्वय मंच के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है. रीडिंग संवाद का उद्घाटन शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने किया. इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अपर सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी (आईआरएस), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक तथा एनबीटी के मुख्य संपादक एवं संयुक्त निदेशक कुमार विक्रम उपस्थित रहे. अपने संबोधन में युवराज मलिक ने कहा कि पठन किसी भी प्रगतिशील समाज की नींव है. उन्होंने सिकंदर, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन से उद्धरण देते हुए बताया कि पुस्तकें ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. वह सोचने, सवाल करने और जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करती हैं. संजय कुमार ने कहा कि पुस्तकों से भरी दीवार से अधिक सुंदर कुछ नहीं होता- और पठन को दूसरे के मन में प्रवेश करने की शक्ति बताते हुए अनेक भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के व्यापक प्रकाशन और पाठकवर्ग के विस्तार का आह्वान किया. उन्होंने नागरिकों से आने वाले 20 साल के भारत की कल्पना करने का भी आग्रह किया. अर्चना शर्मा अवस्थी ने अपने बचपन में पुस्तक मेले में पूरे दिन बिताने की स्मृतियां साझा करते हुए पठन संस्कार विकसित करने में माता-पिता और साहित्य के अध्यापकों की भूमिका पर बल दिया. राजशेखर जोशी ने पुस्तकालयों को प्रौद्योगिकी और व्यक्तिगत पठन मार्गों से समन्वित जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया संवाद के पहले दिन दो समूह चर्चाएं आयोजित की गईं. पाठ्यपुस्तकों से पठन संस्कृति तक- कक्षा की पुनर्कल्पना तथा पुस्तकालय सीखने के केंद्र के रूप में पठन स्थलों का पुनः अधिग्रहण. इन चर्चाओं में नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) के शिक्षा निदेशक निखिल तिवारी, यूनिसेफ इंडिया के शिक्षा विशेषज्ञ दानिश अजीज, टाटा ट्रस्ट्स के पराग इनिशिएटिव की प्रमुख मौलश्री कलोथिया, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के एएसईआर सेंटर की वरिष्ठ परियोजना प्रमुख श्वेता भुटाडा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप राय, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा की विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति की अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) मुनीता रतन तथा स्कॉलास्टिक इंडिया के प्रबंध निदेशक नीरज जैन ने भाग लिया. थीम फर्वेलियन में सेना दिवस के अवसर पर शौर्य, नेतृत्व और बलिदान को प्रतिबिंबित करने वाले सत्रों के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को सैल्यूट किया गया.

भाजपा पैसों को छोड़कर किसी की सगी नहीं है... अखिलेश यादव ने कसा तंज

लखनऊ । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तंज कसते हुए कहा कि ''सत्तारूढ़ पार्टी पैसों को छोड़कर किसी की सगी नहीं है। सपा प्रमुख यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स के अपने आधिकारिक हैंडल से किये गए एक पोस्ट में कहा ''भाजपा अपने संगी-साथियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में काशी की दाल मंडी में हर छोटे-दुकानदार को दल रही है। ये जुल्म और अत्याचार जनता अब और नहीं सहेगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, ''भाजपा पैसों को छोड़कर किसी की सगी नहीं है। सत्ता भी भाजपाइयों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही चाहिए। यादव ने कहा, ''भाजपा विश्वासघात का दूसरा नाम बन गयी है। भाजपा जाए तो हर इंसान चैन पाए! सपा प्रमुख ने इस पोस्ट के साथ दो मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो क्लिप भी साझा की, जिसमें लखीमपुर खीरी जिले के मूल निवासी और (राम मंदिर आंदोलन) कारसेवा के दौरान कथित तौर पर 22 दिनों तक जेल में बंद रहे संजीव जायसवाल नामक व्यक्ति को सरकार पर तंज कसते हुए सुना जा सकता है।

मान सरकार को सीएम नायब सैनी की नसीहत

बोले- ऐसे कुकृत्य करने से पंजाब केसरी की कलम रुकने वाली नहीं

हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस में पंजाब सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे कुकृत्य करने से पंजाब केसरी की कलम रुकने वाली नहीं है। पंजाब केसरी भारत की वो पहचान है जिसकी कलम आतंकवाद के दौरान नहीं रुकी थी। जहाँ सीएम सैनी ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों को कहा कि इनकी बातों में आकर गलत काम ना करें, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ गलत कार्रवाई करना गलत है। बता दें कि पंजाब में पंजाब केसरी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के खिलाफ सरकारी

एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीते दिन आप सरकार पर तीखा हमला बोला है। सीएम सैनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, पंजाब को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने के बाद अब अपने खिलाफ उठ रहे जनआक्रोश से डरी हुई, क सरकार पूरी तरह बौखला चुकी है। सत्ता जाने का भय इतना गहरा है कि अब पंजाब सरकार मीडिया को डराने और दबाने पर उतर आई है। पंजाब केसरी ग्रुप द्वारा लिखा गया यह पत्र इस बात का प्रमाण है कि पंजाब सरकार अपनी विफलताओं, भ्रष्टाचार और कुशासन को छिपाने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता पर सुनियोजित हमला कर रही है।

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा- ईडी के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित

रांची । ईडी और रांची पुलिस के बीच चल रहे विवाद का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को राहत देते हुए रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने राय सरकार और संबंधित पक्षों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जांच के नाम पर किसी केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में बाधा नहीं डाली जा सकती। हाईकोर्ट ने माना कि मौजूद परिस्थितियों में ईडी के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्रवाई से केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है, जो स्वीकार्य नहीं है। इसी आधार पर रांची पुलिस की जांच पर

अंतरिम रोक लगाई गई है। इस आदेश से ईडी के दो अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अब ईडी अधिकारियों की सुरक्षा बीएसएफ के जिम्मे होगी। दरअसल, ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा गुरुवार को रांची स्थित अपने कार्यालय में की गई जांच और छापेमारी के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। ईडी ने याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसी दलील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस पूरे विवाद की शुरुआत पीएचईडी के कर्मचारी संतोष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से हुई थी। संतोष ने आरोप लगाया था कि रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की गई। इस शिकायत के आधार पर रांची के एयरपोर्ट थाना में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ईडी कार्यालय पहुंची थी। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

चुनाव से पहले पीएम मोदी की असम को बड़ी सौगात

अमृत भारत और काजीरंगा कॉरिडोर का देंगे तोहफा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय असम दौरे पर रहेंगे। एक अधिकारी के अनुसार, वे इस दौरान दो अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे और काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। 2026 के पहले छह महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वोत्तर राय का यह एक महीने से भी कम समय में दूसरा दौरा होगा। 17 जनवरी को शाम को पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री शहर के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10,000 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत बोडो लोक नृत्य बागुरुम्बा देखेंगे। अगले दिन, मोदी 6,957 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखने के लिए कालियाबोर जाएंगे। वे डिब्रूगढ़-गोमती नगर (लखनऊ) और कामाख्या-रोहतक नामक दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे और कालियाबोर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी 20 दिसंबर को दो दिवसीय असम दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण किया, जिनके नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। उन्होंने डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे अमोनिया-यूरिया संयंत्र की आधारशिला भी रखी। अपने पिछले दौरे के दौरान, मोदी ने गुवाहाटी और नामरूप में जनसभाओं को संबोधित किया, जिससे 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार हुआ।

बीजेपी को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा, चुनाव का नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली । नितिन नबीन को 14 दिसंबर 2025 को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। 15 दिसंबर को शाह और नड्डा ने उन्हें हाथ पकड़कर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया था। भाजपा को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा। अभी नितिन नबीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी उन्हें ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन सकती है। न्यूज एजेंसी ने 13 जनवरी को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि नितिन नबीन 19 जनवरी को नामांकन भरेंगे। नितिन नबीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था।

भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। तब से वे एक्सटेंशन पर थे। नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने चुनाव का शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक, पार्टी प्रमुख के

कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन चुने जा सकते हैं

चुनाव के लिए नॉमिनेशन 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच भरे जाएंगे और उम्मीदवार उसी दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 20 जनवरी को वोटिंग होगी और उसी दिन नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ही होगी। फिलहाल नितिन नबीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उनकी उम्र 45 साल है। भविष्य में नितिन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता होंगे।

चुनाव आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा, वोट चोरी राष्ट्र-विरोधी काम है- राहुल

नई दिल्ली ।

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों में जैसे-जैसे भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की बढ़त साफ होती जा रही है, विपक्षी खेमे से विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता का भरोसा खत्म होता जा रहा है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती तेज होने के साथ ही, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के भरोसे में कमी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके इन बयानों ने ऐसे समय में एक गरमागरम राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन प्रमुख नगर निकायों में प्रभावशाली बढ़त दिखा रहा है। इस पर गांधी ने कहा, चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में भरोसे के खत्म होने का कारण है। वोट चोरी एक राष्ट्र-विरोधी काम है।

बंगाल में अल्पसंख्यक वोटरों को बनाया जा रहा निशाना- ममता

बंगाल । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राय में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को जानबूझकर मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि अल्पसंख्यक बहुल मालदा जिले में करीब 90 हजार वोटरों के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायत पूरी तरह जायज है, क्योंकि सबसे

ज्यादा निशाना उन्हीं के वोटरों को बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, बल्कि मतुआ, राजवंशी और आदिवासी जैसे पिछड़े वर्गों के वोटरों को भी इस प्रक्रिया में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि मशहूर हस्तियों तक के नाम सूची से हटाने की बात सामने आ रही है। ममता बनर्जी के अनुसार, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और प्रसिद्ध कवि जय गोस्वामी जैसे लोगों के नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी शुक्रवार को उत्तर बंगाल रवाना होने से पहले यह बयान दे रही थीं। वह दार्जिलिंग जिले के माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी इलाके में मल्लकाल मंदिर का उद्घाटन करने वाली हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में चल रहे तनाव पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यह तनाव एक प्रवासी मजदूर के शव के लौटने के बाद शुरू हुआ है, जिसकी कथित तौर पर झारखंड में हत्या कर दी गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि बेलडांगा में लोगों को भड़काने के पीछे कौन है, यह सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि राय में जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे भाजपा का हाथ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में केंद्रीय एजेंसियों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को भाजपा शासित राज्यों में खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और वहां उनकी हत्याएं तक हो रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राय सरकार ऐसे मामलों पर नजर रखे हुए है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हालांकि, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की। शीर्ष अदालत ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। ये एफआईआर कोलकाता में राजनीतिक सलाहकार संस्था आई-पैक और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान कथित बाधा को लेकर दर्ज की गई थीं।

अंगीठी से दम घुटने से बेटा-बेटी की मौत

मुरादाबाद । मुरादाबाद जिले के छजलैट गांव में सर्दी से बचाव के लिए जलाई गई अंगीठी दो मासूमों के लिए काल बन गई। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के दो बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई जबकि तीसरे बच्चे समेत माता-पिता की हालत बिगड़ गई। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। समुचा गांव निवासी जावेद उर्फ पप्पू (35) की मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग पर छजलैट के पास पेट्रोल पंप के समीप चाय की कैंटीन है। घर कैंटीन से कुछ दूरी पर ही है। बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे जावेद पत्नी शाहिस्ता (32) और तीन बच्चों शिफान (6), आहिल (4) और आयरा (3) के साथ कमरे में अंगीठी जलाकर सो गया। रात में अंगीठी से निकली जहरीली गैस के कारण कमरे में घुटन बढ़ती चली गई। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे तक जब परिवार के लोग नहीं जागे तो बराबर के कमरे में सो रहे भतीजे आमिर खान और साले सलाउद्दीन ने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद जावेद ने किसी तरह दरवाजा खोला, वह भी बेहोशी की हालत में था। अंदर पत्नी और तीनों बच्चे अचेत पड़े थे। शोर मचने पर आसपास के लोग पहुंचे और सभी को तुरंत छजलैट के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने आहिल और आयरा को मृत घोषित कर दिया।

मां-बाप अस्पताल में भर्ती

बड़े बेटे शिफान, जावेद और शाहिस्ता को उपचार के बाद होश आया। उनकी हालत में सुधार है। सूचना पर एएसपी अभिनव द्विवेदी और छजलैट पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा और गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनों ने लिखित में देकर दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद शव उन्हें सौंप दिए गए।

क्या बीएमसी में बहुमत जुटा पाएगी भाजपा

मुंबई।

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को विधानसभा चुनाव में मिली जीत कोई तुक्का नहीं थी। वह महिलाओं और युवाओं को साधने की भाजपा बहुत सोची-समझी रणनीति थी जिस पर जनता ने एक बार फिर निगम चुनाव में मुहर लगाया है। इस जीत से राज्य और भाजपा में इस जीत के नायक देवेन्द्र फडणवीस का कद और ऊंचा हो गया है। मुंबई नगर निगम में सत्ता खोने के बाद निगम से ठाकरे युग का अंत होता दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे को समझना पड़ेगा कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से समझौता उनके लिए बहुत भारी पड़ा है। इस चुनाव में बाला साहब ठाकरे के रहे सहे समर्थकों ने भी उद्धव का साथ छोड़ दिया है। ठाकरे परिवार को टकसाल कहे जाने वाले मुंबई नगर निगम से अब ठाकरे परिवार को आर्थिक संजीवनी नहीं मिलेगी। ऐसे में अब शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की राजनीति कितनी आगे बढ़ पाएगी, यह बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने इसके लिए एक बार फिर चुनाव में फॉड होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही पर सवाल खड़ा किया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी इस बात पर हलचल तेज हो गई है कि आखिर कब तक केवल ईवीएम और स्याही पर सवाल उठाकर कांग्रेस नेता अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे? महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश दिया है कि उसे अपनी

110-114 के बीच में फंसी सीटें, सत्ता के लिए करनी पड़ सकती है मशक्कत

चुनावी रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए।

ट्रिपल इंजन का दौर- तुहिन सिन्हा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने अमर उजाला से कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने यह साबित कर दिया है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार का दौर आ चुका है। देश के अनेक राज्यों में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरह नगर निगम चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को जीत मिल रही है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब जनता हर स्तर पर विकास के लिए भाजपा पर भरोसा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने की बजाय जमीनी सचाई को समझते हुए अपने विषय में विचार करना चाहिए।

जैन जी ने भाजपा को चुना- भाजपा

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा और महायुति ने बीएमसी चुनाव में शानदार सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देते

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव

हुए त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र को धरती भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक रही है। मुम्बई में इस जीत के लिए उन्होंने युवाओं का भी धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि मुंबई की जेन जी ने विकसित भारत के लिए वोट किया है। इसके पहले केरल के निगम चुनाव में भी भाजपा को सफलता मिली थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इन चुनावों का एक सीधा संदेश यह भी है कि अब देश की जनता नकारात्मक सोच की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने इंडिया गठबन्धन के अस्तित्व पर भी सवाल उठा दिया है। इन चुनावों में जिस तरह कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि इंडिया गठबन्धन के दलों ने ही गठबन्धन के अस्तित्व को नकार दिया है। राज्यसभा सांसद त्रिवेदी ने कहा कि जाकिर नाईक और अफजल गुरु के साथ खड़े होने के कारण विपक्ष लगातार हार का सामना कर रहा है लेकिन इसके बाद भी वह अपनी गलती को समझना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे की सैद्धांतिक राजनीति से भटकने के कारण उद्धव ठाकरे को इस करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। बाला साहब ठाकरे की सोच से उलट आज उद्धव ठाकरे पाकिस्तान, बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वालों के साथ खड़े दिख रहे हैं।

यही कारण है कि उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि इन चुनाव परिणामों के आने के पहले ही विपक्ष ने चुनाव में मतदान में उपयोग होने वाली स्याही पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी अपनी गलती को स्वीकार करने और उसे ठीक करने की बजाय कभी ईवीएम तो कभी स्याही पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद विकास और राष्ट्रवाद के साथ है, लेकिन विपक्ष मूल बात को समझने की बजाय दूसरे मुद्दे उठा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी राजनीतिक सोच पर मंथन किया जाना चाहिए।